विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक वित्त की भूमिका (ROLE OF PUBLIC FINANCE IN DEVELOPING COUNTRIES)

आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में सार्वजनिक वित्त के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त। राज्य के कार्य व उत्तरदायित्व प्रतिदिन बदल रहे हैं। Laissez faire का समय समाप्त हो चुका है। पुराने समय में राज्य का मुख्य उद्देश्य कानून तथा सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए धन संग्रह करना था। इस सिद्धान्त के अनुरूप सभी आर्थिक निर्णय बाजार में मांग व पूर्ति से अदृश्य रूप में प्रभावित होते थे। सरकार की भूमिका बाजार शक्तियों के कार्य में दखल देने की नहीं थी। वरन् उसकी भूमिका में प्रशासकीय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को बनाए रखना था। परन्तु आज प्रत्येक सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। सरकार का आर्थिक उत्तरदायित्व निरन्तर वृद्धि पर है।

डाल्टन (Dalton) के अनुसार, "सार्वजनिक वित्त का मुख्य सिद्धान्त अधिकतम सामाजिक लाभ है।" "The basic principle of public finance is that of maximum social advantage."

इस प्रकार लोक वित्त की क्रियायें व्यक्ति तथा समाज के जीवन में सभी ओर फैली हुई हैं।

अब प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं को लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक हित को लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक हित को अधिकतम करने में योग देना चाहिए। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि उत्पादन अधिकतम हो और उसका सम वितरण हो जिससे विकास हेतु सभी को समान अवसर प्राप्त हो। लोक वित्त की क्रियायें यथा-प्रति चक्रीय बजट, अनुदान तथा आर्थिक सहायता, लोक ऋण, करारोपण तथा सुनियोजित व्यय व्यवस्था अधिकतम उत्पदान एवं उसके समवितरण को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लोक वित्त की क्रियायें, विकसित तथा विकासशील देशों में, निवेश को प्रोत्साहित करने, आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा सम्पति के समवितरण हेतु, प्रतिपादित की जाती हैं।

अन्त में, कहा जा सकता है कि लोक वित्त आर्थिक विकास को विभिन्न क्रियाओं यथा बचत तथा निवेश की दर में वृद्धि करके, आर्थिक स्थायित्व को प्रोत्साहित करके तथा आय व सम्पत्ति के सम वितरण द्वारा गतिशील बनाता है।

आइये, अब हम लोक वित्त की भूमिका को स्पष्ट करें :

1. बचत व निवेश की दर को बढ़ाना (To increase the Rate of Saving and Investment) – अल्पविकसित देशों में वित्तीय स्रोतों की कमी है और देश की उन्नति में यह सबसे बड़ी बाधा है। बचत घटाने तथा उपभोग बढ़ाने के लिए बहुत से तत्व उत्तरदायी हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या इस का एक मुख्य तत्व है उच्च आय वर्गों के लोग दिखावे की वस्तुओं पर अधिक व्यय करते हैं। इसके अतिरिक्त बचत का अधिक बड़ा हिस्सा अनुत्पादक (Unproductive) मदों पर खर्च होना है जैसे कि सोना व जेवर इत्यादि वस्तुएं एकत्रित करना। इन अनुत्पादक वस्तुओं का उपभोग रोकने के लिए प्रदर्शन की वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाने चाहिए। व्यक्तिगत आय तथा निगम आय पर भी अधिक कर लगने चाहिए। पर्याप्त स्वैच्छिक बचत के अभाव में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों आवश्यक हो जाते हैं।

Scanned with CamScanner

दी इकनामिक बुलेटिन आफ एशिया तथा दी फार इस्ट इस्टेट (The Economic Bulletin of Asia & the Far East Estate) के अनुसार "कराधान ही एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम है जिससे निजी उपभोग व निवेश को घटाया जा सकता है तथा आर्थिक विकास के लिए सरकार को धन उपलब्ध कराया जा सकता है।" **"Taxation, therefore remains the only effective financial instrument for reducing private consumption and investment & transferring resources to the government for economic development."**

2. धन व आय का समान वितरण सुनिश्चित करना (To secure equal distribution of wealth and income) – घन तथा आय का असमान वितरण अल्प-विकसित राष्ट्रों की बहुत बड़ी समस्या है। अमीर लोग अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं। यह स्थिति इन राष्ट्रों के विकास में अवरोधक बनती है। कुछ सीमा तक प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों तथा विलासिता की वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाने से भी आय व धन के असमान वितरण में समानता आ सकेगी। सरकार अनेक क्षेत्रों में निवेश करके गरीबों की आय बढ़ा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार तथा उत्पादन के स्तर भी बढ़ वृद्धि होगी। **प्रो. नरकसे (Nurkse)** के शब्दों में **"आर्थिक विकास के संदर्भ में सार्वजनिक वित्त का मुख्य उद्देश्य है पूंजी निर्माण में राष्ट्रीय आय का अंश बढ़ाना न कि व्यक्तिगत आय व वितरण में परिवर्तन लाना।" "Not a change in the inter personal income distribution but an increase in the proportion of national income devoted to capital formation is the primary aim of public finance in the context of economic development."**

इसके साथ-साथ राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ाने में राजकोषीय उपायों की पुर्नवितरणात्मक भूमिका, समान अवसर तथा संतुलित क्षेत्रीय कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त **आय लोच कर व्यवस्था** (Income elastic tax system) आय के समान वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कर संरचना को लचीला रखा जाए।

3. मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करना (To Counteract inflation) – अल्प विकसित राष्ट्रों में वास्तविक साधनों की मांग व पूर्ति का असंतुलन मुद्रा स्फीति को जन्म देता है। मुद्रा स्फीति से इन राष्ट्रों में आर्थिक व राष्ट्रीय विकास की सारी प्रक्रिया रुक जाती है तथा सारी आर्थिक संरचना नष्ट हो जाती है। इसलिए अल्पविकसित राष्ट्रों के मुख्य दो उद्देश्य हैं आर्थिक वृद्धि तथा स्थिरता। अन्य शब्दों में वृद्धि व स्थिरता दोनों में ही चुनाव नहीं होना चाहिए परन्तु दोनों के आपसी संबंध भी वांछित परिणाम प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुद्रा स्फीति रोकने के लिए सरकार द्वारा बजटीय नीतियां अपनाई जा सकती हैं। प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष कर तथा वस्तुओं पर कर लगाए जाने चाहिए। प्रदर्शन की उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाने जाने चाहिए। इसी प्रकार मुद्रा स्फीति रोकने के अन्य तरीके अपना कर भी इस चुनौती को स्वीकार किया जा सकता है।

4. लोगों का आर्थिक जीवन और सार्वजनिक वित्त (Public Finance and Economic life of the People) – लोगों का आर्थिक जीवन सरकार की गतिविधियों से बहुत प्रभावित होता है। लोगों की उत्पादक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए विविध कर लगाए जाते हैं। सरकार साधारण व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने राजस्व का व्यय करती है। एक तरफ सरकार वित्तीय नीतियां बनाती है ताकि लोगों की आय में अन्तर कम हो सके दूसरी तरफ वह विलासिता की वस्तुओं पर ऊंचे कर लगाती है। शराब व नशे की अन्य वस्तुओं पर भारी कर लगा कर वह इन वस्तुओं का प्रयोग कम करने का प्रयास करती है। इससे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में कमी आती है। कुछ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उन पर करों में राहत भी दे सकती है।

5. पूर्ण रोजगार तथा आर्थिक वृद्धि (Full Employment and Economic Growth) – आधुनिक समय में सभी राज्य कल्याणकारी राज्य हैं तथा उनका मुख्य लक्ष्य नागरिकों को रोजगार प्रदान करके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है। विकासशील देशों में सरकारें पूर्ण रोजगार के अवसर प्रदान कर सकती हैं। इन राज्यों की सरकारें ऊंचे जीवन स्तर तथा आर्थिक वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए कार्य करती हैं। राष्ट्र की आर्थिक नीतियां पूर्ण रोजगार तथा तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो सकती हैं।

Scanned with CamScanner

6. पूंजी निर्माण (Capital Formation) – हम जानते हैं कि एक देश में विकास पूर्णतया पूंजी निर्माण के दर पर निर्भर करता है। इस लिए सार्वजनिक वित्त का सर्वप्रथम तथा परम आवश्यक लक्ष्य है पूंजी निर्माण का संवर्धन। **डा. बलजीत सिंह** के शब्दों में, **"एक अल्प-विकसित देश में, आरम्भिक स्थितियों में सभी आर्थिक नीतियां और उपाय आवश्यक रूप में उत्पादन पर केन्द्रित होने चाहिये तथा राजकोषीय नीति पूंजी निर्माण के उपकरण के रूप में कार्य करें।"** पूंजी निर्माण एक प्रभावी तथा सुनियोजित करारोपण नीति द्वारा बढ़ाया जा सकता है। **आर. नर्कसे** के अनुसार, **"आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक वित्त का लक्ष्य आय असमानताओं में कमी लाना नहीं है परन्तु इस का लक्ष्य आय के उस अनुपात को बढ़ाना है जो पूंजी निर्माण में जाता है।"**

7. नियोजित आर्थिक विकास (Planned Economic Development) – अल्प विकसित विकासशील देशों में उत्पादक साधन मात्रा एवं गुणवत्ता में सीमित होते हैं। सार्वजनिक वित्त देश के योजनाबद्ध आर्थिक विकास में बहुमूल्य योगदान देता है। योजना की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली सार्वजनिक वित्त के यन्त्र के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक वित्त के नियम आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि यह दोनों गतिविधियां घनिष्ट रूप से राज्य से जुड़ी हुयी हैं।

8. आर्थिक असमानताओं में कमी (Reduction in Economic Inequalities) – अल्पविकसित अथवा विकासशील देशों की एक और समस्या है आय अथवा धन का असमान वितरण। इस संदर्भ में सार्वजनिक वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के रूप में सरकार समाज के समृद्ध वर्गों पर ऊंचे कर लगा सकती है तथा इन करों से प्राप्त राशि का उपयोग समाज के निर्धन वर्गों को सस्ते खाद्य पदार्थ, सस्ते निवास स्थान, रोज़गार, निशुल्क चिकित्सा सहायता आदि उपलब्ध कराने में व्यय कर सकती है।

9. साधनों का अनुकूलतम उपयोग (Optimum utilization of Resources) – अल्पविकसित अथवा विकासशील देश दुर्लभ तथा सीमित साधनों का उपयोग न करने अथवा उनको नष्ट होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इस मौलिक समस्या का समाधान उपलब्ध साधनों के अनुकूलतम उपयोग में निहित है। जो उचित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति के अनुपालन द्वारा सम्भव है।

Scanned with CamScanner